विकास के लिए जोखिम: मध्य वर्षीय आर्थिक चिंताएं

साभार : द हिन्दू **12 अगस्त, 2017**

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) के लिए महत्वपूर्ण है।

हाल में नीतिगत परिवर्तनों को देखते हुए, सीईए ने मध्य वर्ष की चिंताओं पर ध्यान देते हुए एक बेहतर प्रयास किया है।

2016-17 के आर्थिक सर्वेक्षण के जारी होने के एक महीने बाद, मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम ने वार्षिक आर्थिक समीक्षा-सह-सूचना रिपोर्ट का दूसरा खंड प्रस्तुत किया है। वैसे इस अंतराल अवधि के साथ सामानों और सेवा करों के महत्वपूर्ण रोल-आउट सहित, डेटा अंक और नीतिगत विकास के साधन प्रदान किए जाने के साथ-साथ परिणामों और पूर्वानुमानों को अपडेट और ताजा करने की स्पष्ट आवश्यकता थी। इसके साथ-साथ मौजूदा वित्तीय वर्ष में विकास के लिए उनका दृष्टिकोण स्पष्ट रूप से अधिक निराश हो गया है। देखा जाये तो वॉल्यूम-I में वर्ष 2017-18 में सकल घरेलू उत्पाद विस्तार 6.75-7.5% की सीमा तक रहने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन इस बार सीईए को कई नए कारकों को संज्ञान लेना पड़ा है जिसने इस सर्वेक्षण में काफी योगदान दिया है, ''जो जोखिम के संतुलन को नकारात्मक पक्ष में स्थानांतरित करते हुए विकास की थोड़ी कम संभावना के साथ ऊपरी छोर के करीब पर पहुँच चुका है।'' हांलाकि, श्री सुब्रमण्यम ने जो भी जोखिमों का जिक्र किया है, उन सभी पर एक त्वरित नजरिए से पता चलता है कि 'जादुई बुलेट' को निर्धारित करने में मुश्किल हो रही है जिसमें कई चिंताएं शामिल है। उदाहरण के लिए, रुपए की असली विनिमय दर की सतत प्रशंसा का मतलब है कि निर्यातकों को तेजी से उन देशों के प्रतिस्पर्धियों के खिलाफ कीमतों पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है जिनकी मुद्राएं डॉलर और यूरो के बीच कमजोर हैं और यह समस्या तब है, जब वैश्विक व्यापार मांग में सुधार अभी भी अधिक मजबूत गति प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। सीईए के मुताबिक, बिजली और दूरसंचार क्षेत्र में कंपनियों के साथ संघर्ष करने वाली कंपनियों की बैलेंस शीटों में बढ़ोतरी होगी और इस तरह के तनाव से उत्पन्न होने वाली गतिविधियों के लिए चलने वाली पूर्वाग्रहों को लेकर तनाव बढ़ती ही जाएगी।

अरविंद सुब्रमण्यम ने जीएसटी का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जीएसटी यानी एक कर प्रणाली को लागू करना एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इस कर प्रणाली को लागू करना प्रशासनिक, राजनैतिक और तकनीकी रूप से प्रशंसनीय हैं। गौरतलब है कि ये छमाही आर्थिक सर्वेक्षण हैं। जीएसटी के कार्यान्वयन के दीर्घकालीन ढांचागत लाभ के अलावा, श्री सुब्रमण्यम का कहना है कि चेकपोस्टों को हटाने के बाद एक क्रॉस-कंट्री लॉजिस्टिक्स बाधा को कम करके एक अल्पकालिक प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। साथ ही यह नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के वास्तविक संचालन से संक्रमणकालीन चुनौतियां कारक को पीछे छोड़ते हुए इसके गति में बढ़ोतरी करेगी। कृषि ऋण छूट और कृषि तनाव सहित अन्य कारकों पर ध्यान देते हुए, जो विकास के दृष्टिकोण को जोखिम में डालते हैं, सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि सरकार की उपचारात्मक प्रतिक्रियाओं के हिस्से के रूप में ''नीति को इस मान्यता से प्रेरित किया जाना चाहिए कि लंबे समय तक क्षितिज के बाद किसान और उपभोक्ता हितों के बीच कोई विरोध नहीं व्याप्त होना चाहिए। खरीद, लाभकारी और स्थिर समर्थन की कीमतों के समर्थन से यह सुनिश्चित करने में मदद मिल सकती है कि उत्पादन और कृषि उत्पादों की कीमतों में मनमाने मूल्य वृद्धि के जोखिम का बहिष्कार किया जा सकता है, इस प्रकार दोनों किसानों और उपभोक्ताओं सुरक्षित हो सकते हैं। सीईए ने सलाह देते हुए इस बात पर जोर दिया है कि ''यह समय इस बात पर विचार करने के लिए उपयुक्त है कि कृषि की आमदनी को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रत्यक्ष समर्थन देना एक अधिक प्रभावी तरीका हो सकता है या नहीं।'' अंततः, उनका तर्क यह था कि इससे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा त्वरित और काफी मौद्रिक सहजता, जिसमें मौजूदा 6% से 4.25-5.25% के बीच की नीति दरों में कटौती शामिल हो, से अर्थव्यवस्था को पूरी क्षमता और तनावग्रस्त बैलेंस शीट के मुद्दे को हल करने में मदद मिल सकती है।

आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम-II

- संसद में शुक्रवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में किसानों की कर्ज माफी और बिजली व टेलिकॉम सेक्टर्स में मुनाफे में कमी के कारण अर्थव्यवस्था को खतरे को लेकर चेताया गया है।
- आर्थिक सर्वेक्षण पार्ट-2 में कहा गया है कि कर्ज माफी और जीएसटी लागू होने से पैदा हुई चुनौतियों के चलते 7.5 फीसदी की आर्थिक विकास दर प्राप्त करने में मुश्किल आएगी।
- सरकार ने फरवरी में आए सर्वेक्षण पार्ट-1 में आर्थिक विकास दर के 6.75 से 7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था। लेकिन, अब इस स्तर तक विकास दर पहुंचने पर संशय जताया गया है।
- इस सर्वेक्षण में वित्तीय घाटा जीडीपी के परिप्रेक्ष्य में 3.2 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। खुदरा महंगाई दर मार्च 2018 तक चार फीसदी से कम रहने का अनुमान लगाया गया है।
- सरकार का कुल खर्च वित्त वर्ष 2019-20 में बढ़कर 26 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच जाने का अनुमान है। वित्त मंत्रालय के एक दस्तावेज के अनुसार, चालू वित्त वर्ष में इसके 21.46 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।
- अरविंद सुब्रमण्यम ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को अवैध घोषित करने के बाद के फैसले की सराहना करते हुए कहा कि इस फैसले के बाद से नए करदाताओं की संख्या में तेजी से बदलाव आया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि नोटबंदी के बाद 5.4 लाख नए करदाता बने हैं। वहीं, राज्यों की किसान कर्ज माफी करीब 2.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंची है।

- इसमें कहा गया है कि इस समय मॉनिटरी पॉलिसी को नरम करने और कर्ज सस्ता किया जा सकता है। साथ ही बताया गया है कि दिवालिया कानून जैसे सुधारों से अर्थव्यवस्था से लाभ होगा।

कौन बनाता है आर्थिक सर्वेक्षण-

- बीते वित्त वर्ष में देश की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था की समीक्षा के बाद वित्त मंत्रालय यह वार्षिक दस्तावेज बनाता है। इसे मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) अपनी टीम के साथ मिलकर तैयार करते हैं। इस बार अरविंद सुब्रमण्यन और उनकी टीम ने आर्थिक सर्वे तैयार किया।

आर्थिक सर्वेक्षण वॉल्यूम- i के मुख्य बिंदु-

- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।
- नोटबंदी के असर से उभरकर भारतीय अर्थव्यवस्था फिर से तेज रफ्तार पकड़कर वर्ष 2017-18 में 6.75 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत के स्तर तक आ जाएगी।
- अप्रत्यक्ष करों के संग्रह में अप्रैल-नवंबर 2016 के दौरान 26.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी।
- वेतन वृद्धि के कारण अप्रैल-नवंबर 2016 के दौरान राजस्व व्यय में हुई तेज वृद्धि।
- खुदरा महंगाई दर लगातार तीसरे वित्त वर्ष के दौरान नियंत्रण में रही।
- खुदरा महंगाई दर वर्ष 2014-15 के 5.9 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में 4.9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई।
- थोक महंगाई दर वित्त वर्ष 2014-15 के 2.0 प्रतिशत से घटकर वित्त वर्ष 2015-16 में ऋणात्मक 2.5 प्रतिशत रह गई और यह अप्रैल-दिसंबर 2016 में औसतन 2.9 प्रतिशत रही।
- वित्त वर्ष 2016-17 में निर्यात 0.7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 198.8 अरब अमेरिकी डॉलर पर।
- वित्तवर्ष 2016-17 में आयात 7.4 प्रतिशत घटकर 275.4 अरब अमेरिकी डॉलर के स्तर पर।
- वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान व्यापार घाटा कम होकर 76.5 अरब डॉलर पर।
- वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में चालू खाता घाटा (सीएडी) कम होकर जीडीपी के 0.3 प्रतिशत पर।
- वित्त वर्ष 2016-17 की प्रथम छमाही में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 15.5 अरब डॉलर की वृद्धि।
- सितंबर 2016 के आखिर में भारत पर विदेशी कर्ज का बोझ घटकर 484.3 अरब डालर रह गया।
- कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2016-17 में 4.1 प्रतिशत रहने का अुनमान।
- वित्त वर्ष 2016-17 में औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर के कम होकर 5.2 प्रतिशत के स्तर पर आएगी, जो पिछले वित्त वर्ष में 7.4 प्रतिशत पर थी।
- कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रदर्शन में वित्त वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही के दौरान कुल बिक्री में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि।
- वित्त वर्ष 2016-17 में सेवा क्षेत्र की वृद्धि दर 8.9 प्रतिशत रहने का अनुमान।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (आईएमएफ) ने भारत की सुनहरी तस्वीर पेश की है। उसके अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार अच्छी होती जा रही है और 2017 तथा 2018 में यह और बेहतर हो जाएगी। गौरतलब है कि 2016 में इकॉनमी की ग्रोथ 7.1% रही थी। लेकिन आईएमएफ का अनुमान है कि 2018 में जीडीपी ग्रोथ 7.7% हो जाएगी, जिससे भारत में रोजगार के काफी अवसर निकलेंगे।
- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने सोमवार को अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक (डब्ल्यूओओ) रिपोर्ट में कहा, 'अप्रैल 2017 के अनुमान के मुताबिक, 2017 और 2018 में भारत की ग्रोथ में अच्छी वृद्धि होने का अनुमान है।'

नोटबंदी के बाद भी हुई अच्छी ग्रोथ

- नोटबंदी के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि शायद उससे इकॉनमी ग्रोथ ना हो पाए, लेकिन सरकार द्वारा अच्छा पैसा खर्च करने और सुधार की वजह से ग्रोथ 7.1% रही, काफी अच्छा है। 2018 में भारत 7.7 फीसदी की दर से विकास करेगा।

आईएमएफ ने भारत को इन चीजों में सुधार करने के लिए कहा

- हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुधारों की सूची भी दी है, जिसमें नोटबंदी के बाद कैश का फुल फ्लो होना आवश्यक है, लेबर और प्रोडक्ट मार्किट को लचीला बनाना, मैन्युफैक्चरिंग बेस में विस्तार, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार आदि शामिल हैं।
- अप्रैल में, नोटबंदी के कारण, आईएमएफ ने 2017 के लिए भारत की वृद्धि दर 0.4 प्रतिशत घटाकर 7.2 प्रतिशत कर दी थी। आईएमएफ इस साल 3.5 प्रतिशत ग्लोबल ग्रोथ रेट का अनुमान लगा रहा है, जो 2018 में 3.6 प्रतिशत हो सकता है।

संभावित प्रश्न

''हाल ही में वर्तमान सरकार द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण का दूसरा भाग संसद में पेश किया गया, जिसमें एक तरफ महंगाई कम होने की संभावना व्यक्त की गयी है, तो दूसरी तरफ किसानों की कर्ज मॉफी से अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की संभावना भी व्यक्त की गयी है।'' इस कथन के सन्दर्भ में सरकार द्वारा इस चुनौती से निपटने के लिए क्या अपेक्षित कदम उठाये जाने चाहिए? चर्चा कीजिये। (200 शब्द)

705, IInd Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, New Delhi - 110009
Ph.: 011 - 27658013, 9868365322